भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 690

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत जल की आपूर्ति न होना

†690. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

श्रीमती भारती पारधीः

श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत नल कनेक्शन लगाने के बाद भी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत नए नल कनेक्शनों का प्रावधान कुछ राज्यों में समाप्त कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 25.11.2024 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत लगभग 12.07 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 25.11.2024 तक, देश के 19.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.30 करोड़ (79.11%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इस मामले में राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई थीं, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों ने सूचित किया है कि मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए नल कनेक्शनों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने में मुख्य रूप से निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

i.) स्रोत संवर्द्धन का कार्य अभी भी प्रगति पर है जिसके कारण विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के दौरान मौजूदा पेयजल आपूति स्रोतों में जल की कम और घटते उत्पादन के कारण अस्थायी रूप से अपर्याप्त जल सेवा प्रदायगी हो रही है। जल उपलब्धता में यह कमी जल आपूर्ति प्रणालियों पर मौजूदा दबाव को बढ़ाती है, जिससे संभावित कमी और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ जाता है।

ii.) ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनाओं के संचालन और रखरखाव की चुनौतियां, असंगत बिजली आपूर्ति, अपर्याप्त धूप सौर-आधारित प्रणालियों को प्रभावित करती है, जिससे सेवा प्रदायगी की विश्वसनीयता के मुद्दों में वृद्धि होती है। इसके अलावा, रखरखाव कार्यक्रम की कठिनाइयों, उपकरणों के टूटने और कार्यबल प्रबंधन के संबंध में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

iii.) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में भारी वर्षा और बाढ़ जैसी खराब मौसम परिस्थितियाँ जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को नुकसान का एक प्राथमिक कारण हैं।

iv.) खराब अंतर-विभागीय समन्वय के कारण जल आपूर्ति अवसंरचना को क्षति, जैसे कि सड़क निर्माण और अन्य विकास परियोजनाओं के दौरान पाइपलाइन को क्षति।

v.) लंबित मुख्य निर्माण परियोजनाओं को पूरा किए बिना नल कनेक्शन की अग्रिम सूचना। शोधन संयंत्रों और भंडारण टैंकों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक घटक जल आपूर्ति क्षमताओं को बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन सुविधाओं के चालू होने में हुई देरी ने समग्र आपूर्ति को बाधित किया है, जिससे सेवा स्तर प्रभावित हुआ है और जल वितरण में असमानताएं पैदा हुई हैं।

(ग) और (घ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को पांच वर्ष अर्थात 2019-20 से 2023-24 तक मंजूरी दी थी। अब तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुदुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात यहाँ 100% परिवारों को नल जल आपूर्ति प्राप्त हो रही है और शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कार्य संपूर्णता योजना के अनुसार मिशन के पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के विस्तार पर विचार किया जा रहा है जिसके दौरान उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

(ङ) और (च) अभी तक इस विभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नए नल कनेक्शनों के बंद होने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*****